www.wagadsandesh.com

वागड़ संदेश

Tital Code : RAJHIN27802

जन मन की आवाज

सम्पर्क

ई-पेपर मे खबरे व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें

ई-मेल - editorwagadsandesh@gmail.com

☎ 8890633631
9309255545
6351581818

वर्ष-1 अंक-159 सागवाड़ा, शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 अवधि: हिन्दी ई-पेपर पृष्ठ-1, मूल्य-10 रु. (वार्षिक)

रीट खराबे से प्रभावित युवाओं को मुआवजा की मांग

समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर टीएसपी क्षेत्र के युवाओ की हालत और मांग को लेकर जानकारी दी

डूंगरपुर। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बेरोजगारों के हितो के रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन समानता मंच ने फसल खराबे के मुआवजे और दुर्घटना मुआवजे की तर्ज पर रीट खराबे से प्रभावित युवाओ को मुआवजा देने की मांग उठाई है। डूंगरपुर में समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर टीएसपी क्षेत्र के युवाओ की हालत और मांग को लेकर जानकारी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

क्षेत्र के 15 हजार 500 शिक्षित बेरोजगारों ने रीट परीक्षा में आवेदन पर लाखो रुपये और परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग व् किताबो पर करोडो रुपये खर्च किये। लेकिन सरकार की विफलता के कारण इन युवाओ की मेहनत पर पानी फिर गया वही उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। प्रेसवार्ता के माध्यम से समानता मंच ने सरकार के समक्ष मांग रखी है कि टीएसपी क्षेत्र में निवास करने वाले 15 हजार 500 अभ्यर्थियों को सरकार फसल खराबे के मुआवजे और दुर्घटना मुआवजे की तर्ज पर 25 हजार प्रति अभ्यर्थी मुआवजा दे साथ ही रीट परीक्षा वापस होने तक हर अभ्यर्थी को 3 हजार रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाए। दिग्विजय सिंह ने टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के युवाओ के हितो को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को राजनीती से ऊपर उठकर इनकी सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। दिग्विजय ने बताया कि समानता मंच अपनी मांगो को लेकर टीएसपी क्षेत्र के विधायको से मिलेगा वही जरुरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किये जाएंगे।

विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा

रीट पेपर लीक गैंग का पता लगाना चाहिए : सीपी जोशी

जयपुर। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का आज भी हंगामा जारी रहा। बीजेपी विधायक रीट की सीबीआई जांच पर अड़े हैं, इसे लेकर सदन में दिन भर विरोध जारी रखा, हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन चला। । स्पीकर के प्रयासों के बावजूद भी गतिरोध नहीं टूट सका, उधर सरकार ने रीट धांधली की सीबीआई जांच करवाने से इनकार कर दिया है। इस बीच रीट विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कह दिया कि पेपर लीक गैंग का पता लगाना चाहिए। सीपी जोशी ने कहा कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, उन्हें नौकरी मिले, यह सुनिश्चित हो। सरकार उस पर बयान दे कि परीक्षाओं को गैंग से कैसे मुक्त कराएगी। सीबीआई जांच की विपक्ष की मांग पर मैं नहीं जाता, लेकिन नौकरी में फेयर सलेक्शन हो, यह गंभीर मुद्दा है। पेपर लीक के अपराधियों को चिन्हित करना जरूरी है। सदन में गतिरोध खत्म कर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है। सरकार की भी सुननी चाहिए और हमें इस पर विचार करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। वहीं REET पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने साफ कह दिया कि सरकार रीट की सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में रीट पर जवाब देने को तैयार है। हम बीजेपी राज के कारनामे भी गिनाएंगे, हिम्मत है तो करिए मुकाबला। सदन में बहस कीजिए। यह सब दिल्ली के इशारे पर किया जा रहा है। धारीवाल ने कहा कि बीजेपी राज के वक्त में जो कारनामे हुए हैं हम एक एक गिनाएंगे। आज सीबीआई को जांच देने का मतलब क्या है? बीजेपी राज में 5 बार पेपर लीक हुए, उस वक्त तो सीसीबाई को मामला छोड़ो एसओजी तक को नहीं दिया तो अब सीबीआई को क्यों दें। सरकार जवाब देने और बीजेपी राज का कच्चा चिट्ठा खेलने को तैयार है। यह सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई

डूंगरपुर। जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ओर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश की उपस्थिति आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलक्टर चौधरी ने विकास अधिकारियों से कहा कि नरेगा योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्य को ऑनलाइन एवं अपूर्ण कार्य को 28 फरवरी तक पूरा करे साथ ही अधिक से अधिक संख्या में कार्यरत श्रमिकों के 100 दिवस पूर्ण करवाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए। बैठक में कलेक्टर चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन, विधायक मद, सांसद मद, 14 वा व 15 वित्त व अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए पूर्ण कार्यो की उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्रों को 28 फरवरी तक भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने नवीन पंचायत समिति भवन व नवीन ग्राम पंचायत भवनों को लेकर आवश्यक निर्देश देते हुए अच्छे कार्यो के संकलन कर भेजने के निर्देश दिए।

मातृ शिशु अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं का निरिक्षण किया

डूंगरपुर। केंद्र सरकार के लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत डूंगरपुर जिले के मातृ शिशु अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं का निरिक्षण करने शुक्रवार को दिल्ली ढ्ढड्ढस्र्स से 2 सदस्यों का केन्द्रीय दल डूंगरपुर पंहुचा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ संचालित मातृ शिशु अस्पताल के निरिक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ श्रीकांत असावा और अधीक्षक डॉ महेंद्र डामोर भी मौजूद रहे। निरिक्षण के दौरान प्रिंसिपल डॉ. असावा ने टीम को अस्पताल भवन की जानकारी दी वही मरीजो को दी जा रही सुविधाओं से भी अवगत कराया। लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल का निरिक्षण करने आये डॉक्टर रेडबोन लाला और डॉक्टर आनंदी ने एमसीएच की ग्रेडिंग देने के लिए करीब 100 से अधिक पैरामीटर पर अस्पताल का निरीक्षण किया। एमसीएच के निरीक्षण के दौरान वहां पर महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं, ओपीडी केंद्र , जांच केंद्र, ऑपरेशन थिएटर, परिवार कल्याण थियेटर, पोस्ट डिलीवरी वार्ड और कैंसर वार्ड का निरीक्षण कर अलग-अलग ग्रेडिंग की। निरिक्षण के बाद टीम रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी वही सब कुछ सही रहा तो डूंगरपुर मात्र एवं शिशु अस्पताल को क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और यदि कमिया मिली तो उन्हें सुधरने के निर्देश दिए जाएंगे।

वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में लूट में हुई कमी तो चोरी व नकबजनी की वारदातें बढ़ी

डूंगरपुर। जिले में चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातो में लगातार इजाफा हो रहा है । जिले में वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में लूट में हुई कमी तो चोरी व नकबजनी की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है । महीनो गुजर जाने के बाद भी पुलिस करीब 40 प्रतिशत वारदातों को खोलने में नाकाम साबित हुई है। हालाकि पुलिस की ओर से रिकवरी व चालानी प्रतिशत बेहतर रहा है । डूंगरपुर जिले में बदमाशो के हौसले बुलंद है । जिले में बदमाशो ने चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातों को अंजाम देते हुए पुलिस और लोगो की नाक में दम कर रखा है । डूंगरपुर पुलिस के चोरी,लूट व नकबजनी के प्रतिवर्ष के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे है । पुलिस के आंकड़ो के अनुसार डूंगरपुर जिले में वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में लूट में हुई कमी तो चोरी व नकबजनी की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है ।

आइये बताते है इस वर्ष कितनी हुई चोरी,नकबजनी व लूट की वारदाते डूंगरपुर जिले में प्रॉपर्टी ओफेंसिव केस

वर्ष	लूट	चोरी	नकबजनी	कुल
2019	45	145	56	246
2020	3।	124	31	192
2021	36	129	3।	202

इधर जिले में बढती चोरी, नकबजनी व लूट के बढ़ते मामलों को लेकर डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने चिंता जताई है । हालाकि एसपी सुधीर जोशी ने बताया की पुलिस की ओर से वारदातों को खोलने का काम किया जा रहा है । और उसी का कारण है की चोरी,नकबजनी व लूट की वारदातों में पुलिस की ओर से रिकवरी व चालानी प्रतिशत बेहतर रहा है।

एसपी सुधीर जोशी ने बताया की वर्ष 2021 में माल बरामदगी का प्रतिशत ।6 फीसदी तो वही चालानी प्रतिशत 5। फीसदी रहा है । इधर एसपी सुधीर जोशी ने बताया की कई वारदाते अभी खुलना शेष है जिन्हें खोलने के साथ इन वारदातों की रोकथाम के लिए भी पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है ।

राजनीतिक नियुक्ति वालों को मंत्री का दर्जा नहीं देंगे: गहलोत

जयपुर। जिन विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां मिली है उन्हें सरकार कोई सुविधा नहीं देगी। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजनीतिक नियुक्तियां पा चुके कांग्रेस नेताओं की बैठक में कहा- विधायकों को हम कोई दर्जा नहीं दे पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की क्लीयर रूलिंग है। जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। गहलोत ने कहा कि आप मुझे फीडबैक दोगे, क्योंकि अधिकारी सही बात नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप जीत रहे हो और सब जानते हैं कि क्या हुआ।

नवाचार- पढ़ेगा डूंगरपुर-बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत होगी

डूंगरपुर। जिले में बच्चों को पढ़ाई के साथ उनकी झिझक दूर करने जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने एक नवाचार किया हैं। 14 फरवरी से जिले में पढ़ेगा डूंगरपुर-बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत होगी। अभियान में स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम होंगे। अभियान को लेकर प्रेसवार्ता में कलेक्टर शुभम चौधरी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों में अजीब झिझक है। बच्चें स्कूल में बोल नहीं पाते है या फिर सवाल-जवाब नहीं कर पाते है। इस वजह से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों में इसी कमी को दूर करने के लिए 14 फरवरी से पढ़ेगा डूंगरपुर-बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में कक्षा 6 से 8वी तक के बच्चों को पुस्तकालय, वाचनालय से जोड़ा जाएगा। हर छात्र-छात्रा को दो सप्ताह में कम से कम एक बार कविताओं, कहानियों को अपने अंदाज में पेश करना होगा। साथ ही बच्चो में सवाल-जवाब की क्षमता भी विकसित की जाएगी ।उन्होंने बताया कि जिले में बालक-बालिकाओं में पढने व अभिव्यक्ति के कौशल का श्रेष्ठ विकास करने हेतु सभी अधिकारियों को अपने पर्यवेक्षण के दौरान अवलोकन करने के निर्देश प्रदान किये गये है। साथ ही इस बात के लिये भी पाबंद किया गया है कि कक्षा के प्रत्येक बालक-बालिका को दो सप्ताह में कम से कम एक बार अभिव्यक्ति का अवसर अवश्य मिलें। जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पठन और अभिव्यक्ति कौशल विकसित कर बच्चों का आत्मविश्वास विकसित करना है, जिससे भविष्य में केरियर के दौरान उन्हें पूर्ण सहयोग मिल सकें।

बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा मेले की स्वीकृति जारी करने की मांग

भाजपा ने सरकार ओर प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप

सीमलवाड़ा। वागड़ प्रयाग व त्रिवेणी संगम स्थल के नाम से प्रख्यात बेणेश्वर धाम पर हर साल लगने वाला माघ पूर्णिमा को सरकार द्वारा स्थगित किए जाने का भाजपा ने विरोध जताया है। धार्मिक अनुयायियों सहित जनजाती अंचल का महाकुंभ माने जाने वाले बेणेश्वर धाम पर सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना का हवाला देकर मेला लगाने व दुकानें लगाने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है। जिसको लेकर भाजपा द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी हनुमान राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक अनुयायियों को आने जाने में छूट मिली है। क्योंकि अजमेर व डूंगरपुर दोनों ही राजस्थान में आते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा हिंदुओं के आस्था का केंद्र बेणेश्वर धाम जहां पर हिंदू समाज के लोग अपने सगे संबंधियों का उत्तर क्रिया करते हैं। पर पाबंदी लगाना सरकार के सौतेले व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अजमेर में कोविड गाइडलाइन की पालना को आधार मानते हुए स्वीकृति प्रदान की है ।चूंकि जिले में कोविड-19 सक्रमत्ता मैं शिथिलता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले उक्त मेले में आमजन के लिए पाबंदी हटा कर मेले व दुकान में लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सीमलवाड़ा प्रधान कारी लाल ननोमा, जिला महामंत्री नानुराम परमार, गोरधन पाटीदार, सरपंच संघ अध्यक्ष बाबूलाल डामोर, सीमलवाड़ा सरपंच विजयपाल डोडियार पंकज कलाल,लक्ष्मण डामोर,मगन लाल, लोकेंद्र सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जयपुर में बहू ने ही रची थी लूट की साजिश

जयपुर। सांगानेर थाना इलाके में हुई 2 किलो सोने की लूट और 11.30 लाख रुपए की नकदी मामले में पुलिस ने रामधन सैनी के भांजे निखिल सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों को संदिग्ध मानते हुए सभी की कॉल डिटेल खंगाली तो परिजनों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने शुक्रवार रात 10:30 बजे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कोरोना से 24 घंटे में 9 मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना के केसों की संख्या में कमी आने के साथ अब मौत के केस भी धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2890 नए केस मिले हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 23 दिन में सबसे कम मौत की संख्या है। राज्य में शुक्रवार को 6632 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके बाद एक्टिव केस की संख्या घटकर 25 हजार 779 पर पहुंच गई। राज्य में आज पॉजिटिविटी रेट भी 7 फीसदी से कम रही। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो शुक्रवार को सबसे ज्यादा 753 मरीज जयपुर में मिले हैं। नागौर में 202, जोधपुर 199, सीकर-उदयपुर में 136-136 और अजमेर में 107 केस मिले हैं। शेष सभी जिलों में 100 से कम केस आए हैं। आज जयपुर में 3 और अजमेर, बीकानेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, सिरोही में एक-एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है। राज्य में शुक्रवार को 41 हजार 914 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद टेस्ट पॉजीटिविटी रेट 6.90 फीसदी रहा।

कोयला आपूर्ति के लिए सभी वैकल्पिक उपाय सुनिश्चित किए जाएं: मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजलीघरों को मांग के अनुरूप कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश में कहीं भी विद्युत उत्पादन में बाधा नहीं आए। इसके लिए तमाम वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाए। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोयला आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा राज्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर उचित समन्वय करें। उन्होंने कहा कि कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड से लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोयला खदानों से कोयले के शीघ्र उठाव के लिए रेलवे से प्रदेश को और अधिक संख्या में रैक उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही आयातित कोयले अथवा शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए बिजली खरीद सहित प्रदेश के निजी थर्मल प्लांटों से उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी प्रदेश में विद्युत की सुचारू आपूर्ति के लिए नए कोल ब्लॉक्स आवंटन, कोयले के सुचारू परिवहन एवं भण्डारण की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें। अधिकारी सुनिश्चित करें कि विद्युत इकाइयों के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले का भण्डारण उपलब्ध हो ताकि कोयले की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कोल इंडिया सहित अन्य कंपनियों को भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं को भी समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में कोयला संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसे देखते हुए केंद्र सरकार एवं कोल माइन्स आदि से निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। रेलवे से भी रैक की संख्या बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोल इंडिया की सहायक एनसीएल एवं एसईसीएल द्वारा तापीय विद्युत गृहों को 9 रैक प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है। पारसा ईस्ट एवं कांटा बेसिन कोल ब्लॉक से 8 से 9 रैक प्रतिदिन आपूर्ति हो रही है। फरवरी 2022 के बाद पारसा ईस्ट कांटा बेसिन ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति बंद होने की संभावना है। ?से में कोल इंडिया लिमिटेड से अतिरिक्त कोयला आवंटन के लिए संपर्क किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, चेयरमैन डिस्कॉम्स भास्कर सावंत, आरवीयूएनएल के सीएमडी आर.के. शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

4 निलम्बित बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना

जयपुर। भाजपा के 4 विधायकों रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह आक्या और अविनाश गहलोत ने निलम्बन के विरोध और रीट की सीबीआई जांच की मांग पर विधानसभा के गेट पर धरना दिया। चारों विधायकों ने नारे लगाए- रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में.....विधायकों ने कहा कि चाहे सरकार 4 विधायकों को निलम्बित करे या 40 विधायकों को निलम्बित कर दे। बीजेपी का संघर्ष सीबीआई जांच तक जारी रहेगा ।बीजेपी विधायकों ने कहा कि रीट मामला 26 लाख युवाओं और 1 करोड़ लोगों से जुड़ा है। यह प्रदेश और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी पार्टी का फैसला है कि इस मुद्दे पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी यह फैसला लिया गया है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। निलम्बन वापस नहीं लेने पर विधायक मदन दिलावर ने कहा सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है।

बड़े-बड़े मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं । रीट पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं,तो उनकी जांच होनी चाहिए। दिलावर ने कहा राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मुख्यमंत्री पदाधिकारी हैं। इसलिए जांच जरूरी है।